

संपादकीय

मौत के बोरवेल

ऐसे समय में जब देश—दुनिया नये साल के जश्न में छूबने जा रही है मध्यप्रदेश व राजस्थान में खुले बोरवेल में गिरने से हुई दो बच्चों की मौत विचलित करती है। राजस्थान के दोसा जिले और मध्यप्रदेश के गुना की घटनाएं पहली बार नहीं हुई हैं। गाहे—बगाहे ऐसी खबरें पूरे देश से आती हैं। यह सोचकर ही मन सिहर उठता है कि कोई बच्चा कैसे एक अंधी सुरंग में भूखे—प्यासे, अपर्याप्त औंकसीजन व बिना हिले—डुले कुछ दिन मौत की प्रतीक्षा करता होगा। भय व घुप्प अंधेरे में बच्चा किन मानसिक व शारीरिक यातनाओं से गुजरता होगा, सोचकर भी डर लगता है। लेकिन फिर भी हमारा संवेदनहीन समाज व लापरवाह तंत्र इस ब्रास्टी को गंभीरता से नहीं लेता। जिस बोरवेल को खुदवाने में लाखों रुपये खर्च होते हैं, उसका मुंह बंद करने के लिये चंद रुपये खर्च करने में लोग आपराधिक लापरवाही दिखाते हैं। राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल में गिरी तीन साल की बच्ची को एक सप्ताह बाद भी न निकाला जाना तंत्र की विफलता को दर्शाता है। निस्संदेह, यह अभियान जटिल बताया जाता है और बारिश ने राहत कार्य में बाधा डाली, लेकिन शुरुआत में प्रशासन की शिथिलता पर सवाल उठे हैं। ऐसे अभियानों में राष्ट्रीय आपदा निरोधक बल तथा स्थानीय सुरक्षा बलों की नाकामी गाहे—बगाहे उजागर होती रहती है। निस्संदेह, ऐसे संकटों में तत्काल कार्रवाई और राहत—बचाव कार्य को आधुनिक तकनीक से शुरू करने की जरूरत महसूस की जाती रही है। यही वजह है कि आए दिन होने वाले बोरवेल हादसों के महेनजर देश की शीर्ष अदालत ने वर्ष 2010 में इस बाबत दिशानिर्देश जारी किए थे ताकि ऐसे हादसों को टाला जा सके। जिसमें बोरवेल के चारों ओर बाड़ लगाने तथा मजबूत बोल्ट के साथ स्टील कवर लगाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद आए दिन बोरवेल में बच्चों के गिरने के मामले सामने आ रहे हैं। जाहिर किसान व स्थानीय प्रशासन सुधीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। अन्यथा ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न होती। निस्संदेह, देश के विभिन्न भागों में बोरवेल हादसों का सामने आना जहां निगरानी करने वाले विभागों की लापरवाही को दर्शाता है, वहीं उन लोगों के आपराधिक कृत्य को भी दर्शाता है, जो बोरवेल का मुंह खुला छोड़ देते हैं। वहीं हादसे हमारे समाज में चेतना के अभाव को भी दर्शाते हैं कि खुले बोरवेल के खिलाफ आम लोगों के स्तर पर आवाज नहीं उठायी जाती। यह भी उल्लेखनीय है कि सिंचाई विभाग राज्यों का विषय होने के कारण इसमें केंद्र सरकार का दखल नहीं हो पाता। एक अनुमान के अनुसार देश में करीब पौने तीन करोड़ बोरवेल हैं। जिसमें से बड़ी संख्या में सूख चुके हैं। जिन्हें गैरजिम्मेदार लोगों द्वारा खुला छोड़ दिया जाता है, जो कालांतर हादसे की वजह बन जाते

क्या बीजेपी की विजय के चकरे ने अब उल्टी दिशा में घूमाना शुरू कर दिया है? पर ऐसा भी नहीं है। इस वर्ष आधं प्रदेश, अरुणाचल, ओडिशा, सिक्किम, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभाओं के चुनाव भी हुए। जम्मू-कश्मीर में एक दशक के बाद विधानसभा चुनाव हुआ था। राज्य में अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पहला चुनाव था। इस बार मतदाताओं ने वोटिंग के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शानदार वापसी की। वहीं हरियाणा, जम्मू-कश्मीर के जम्मू क्षेत्र और खासतौर से महाराष्ट्र के परिणामों ने बीजेपी को भारी राहत प्रदान की। प्रधानमंत्री बनने के नरेंद्र मोदी ने गृह, रक्षा, वित्त और विदेश विभाग अपने उन्हीं सहयोगियों को सौंपे जो पिछले कार्यकाल में उनके मंत्री थे। इससे उन्होंने यह जाहिर कर दिया कि जैसा चल रहा था, वैसा ही चलेगा। बहरहाल केंद्र में गठबंधन की मजबूतियों के कारण इस सरकार को अब अगले चार साल तक अपने राजनीतिक-कार्यक्रमों को लागू करने में वैसी स्वतंत्रता नहीं होगी, जैसी पिछले दस वर्षों में रही। साल के अंत में सरकार ने 'एक देश, एक चुनाव' कार्यक्रम के साथ संविधान-संशोधन का विधेयक पेश किया है। उसे फिलहाल संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। अब उसे पास कराने के लिए जिस विशेष दो-तिहाई बहुमत की जरूरत भविष्य में होगी, उसके लिए सरकार को अपने गठबंधन सहयोगियों के अलावा दूसरे दलों के समर्थन की जरूरत भी है। साल की शुरुआत 22 जनवरी को अयोध्या के राममंदिर की स्थिति के साथ हो गई। लगता था कि अयोध्या-विवाद का समाधान जाने के बाद बीजेपी के पारस्पर मसला कम हो गया है, पर ऐसा नहीं। वाराणसी के ज्ञानवापी, के कृष्ण जन्मभूमि, राजस्थान अजमेर शरीफ और अब संभवतः विवादों ने राष्ट्रीय-परिदृश्य का लिया है। इन विवादों के संभवतः साल के आखिरी महीने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख भागवत के एक बयान ने एक बहस को जन्म दे दिया है।

संभवतः अगले साल राष्ट्रीय-परिदृश्य को प्रभावित रहेगी। मोहन भागवत ने 19 फरवरी को पुणे में 'हिंदू सेवा महोत्सव' उद्घाटन के दौरान 'मंदिर-मस्जिद के रोज नए निकालकर कोई नेता बनना चाहिए' दुनिया को दिखाना है कि हम साथ रह सकते हैं। अब वर्चस्व जमाना खद्दम हो गया है। यह पुरानी लड़ाइयां हैं, इन्हें भूलकर सबको संभालना चाहिए।

भागवत के बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कुछ धर्मगुरुओं ने उत्तर भारत के सर्द माहौल में गर्मी पैदा कर दी। इस गर्मी के साथ साल के उत्तर भाग लौटा दिया गया है। डॉ. भीमराव अंबेडकर को लेकर दूर्वाला भूई तल्खी भी साल की महाघटनाओं में एक है। अंबेडकर की विरासत को लेकर राजनीति में आया हुआ है। अमित शाह की फैली के बाद संसद के परिसर में

हांगी। री को धापना आया कि न हो न एक तरसा है मथुरा न के लाल के गोंधों घेर दर्भ में अष्ट्रीय मोहन 5 और 5, जो के करती देसंबर 'व' के कहा, विवाद बाहता हुए, हमें एक चक्र का ह सब तर हमें बागवत व्यमंत्री वर्चार्यों तर के दी है। अंत में तर पैदा त्वपूर्ण तर की तूफान टेप्पणी विरोध प्रदर्शन के दोरान दोनों पक्षों के बीच हाथापाई तक हुई। अगले साल की पहली तिमाही में ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए यकीनन सभी दल इस मुद्दे को उठाना जारी रखेंगे। इस तूफान के लक्षण 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले प्रकट होने लगे थे, जब कांग्रेस ने जाति और संविधान की रक्षा को अपना मुद्दा बनाया। कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी '400 पार' इसलिए चाहती है, ताकि वह संविधान को खत्म कर सके। संविधान खत्म होगा, तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। माना जाता है कि आरक्षण खत्म होने के भय ने दलित वोटर को 'इंडिया' गठबंधन की शरण में जाने को प्रेरित किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफतारी और जेल से बाहर आने के बाद उनके इस्तीफे ने भी राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई है। केजरीवाल के अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इस साल जेल जाना पड़ा, पर विधानसभा चुनाव में उनकी जीत ने इस कष्ट को काफी कम कर दिया। चुनाव का वर्ष होने के कारण इस साल पहले फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया और फिर नई लोकसभा के गठन के बाद जुलाई में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्ण बजट पेश किया। अर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति के क्षेत्र में यह साल भारत के लिए उत्साहवर्धक रहा। अर्थव्यवस्था ने 2024 में अपनी रिकवरी जारी रखी, देश ने 7 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर्ज की, जिससे यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख

आमत शाह का रणनीति

બીતે વ

हर नए साल के साथ इसके यांकन की परंपरा है। इस लिहाज अगर बीते हुए यानी साल 2024 का यांकन करेंगे तो कई बिंदुओं पर हमें आशा हाथ लगेगी तो कई उपलब्धि और कामयाबियों का भी जिक्र होगा। लाल आतंक के रूप में विद्युत सलवाद पर नकेल बीते हुए साल उपलब्धि कही जा सकती है। का श्रेय निश्चित तौर पर गृहमंत्री नेत शाह को जाता है, लेकिन में भूमिका राज्यों की भी कम नहीं है। बीते साल सुरक्षा बलों की रेखाई में भारी संख्या में नक्सली तो मारे गए हैं या फिर गिरफ्तार हर गए हैं। इसके साथ ही कई नक्सलियों ने समर्पण करके मुख्यमंत्री की जिंदगी को अपनाया है। नक्सली आतंक पर कामयाबी के पीछे तीन-स्तरीय रणनीति, जिसके तहत सबसे पहले नक्सलियों पर समर्पण का दबाव बनाया गया। अगर इसके बावजूद नक्सली नहीं मानता तो उसकी पहले गिरफ्तारी के लिए नीति बनाई गई। इसके बावजूद अब नक्सलवादी नहीं माने तो उनके लाल निर्णयक मुठभेड़ की तैयारी

तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के हजारों गांवों को सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा गया। इन गांवों में बुनियादी सहूलियतों को बहाल किया गया। इसकी वजह से इन इलाकों के स्थानीय निवासियों की जिंदगी की कठिनाइयां कम हुईं। इसकी वजह से उन्होंने विकास की दारा को अपनी आंख से देखा और भारतीय राष्ट्र राज्य के बारे में उनकी धारणा बदली। इस धारणा को बदलने के बाद सुरक्षा बलों के लिए नक्सलियों को रोकने के लक्ष्य में बड़ी सफलता मिली। नक्सलियों को लोक समर्थन कम हुआ। इसके साथ ही सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मुश्यधारा में शामिल करने के लिए आर्थिक सहायता और पुनर्वास योजनाओं की शुरुआत की। इसके तहत 15,000 आवास बनाने का फैसला लिया गया, साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में रोजगार को लेकर विशेष योजनाएं चलाई गईं। इससे न केवल हिंसा में कमी आई, बल्कि स्थानीय लोगों की जिंदगी की दुश्वारियां कम हुईं। इसकी वजह से उन लोगों का मन बदला, जो माओवाद की राह पर नक्सलवादी वैचारिक बहकावे में चल

रोजगार की स्थितियां बेहतर बनाने और विकास की धारा को बहाने के बावजूद लंबे समय से नक्सल प्रभावित रहे लोगों के लिए मुख्यधारा में लौटना या मुख्यधारा के प्रति भरोसा बनाना बिना सुरक्षा सुनिश्चित किए संभव नहीं था। सरकार ने इस मोर्चे पर भी काम किया और सुरक्षा बलों की प्रभावी उपस्थिति हर संभव स्तर पर की। नक्सल प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा सहूलियत को बढ़ावा देने के लिए युद्धस्तर पर कार्यक्रम चलाए गए। पहले इन इलाकों के लिए स्कूल और अस्पताल सपना थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। इसके साथ ही, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना भी की गई है। जहां आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। इससे भी नक्सल प्रभावित इलाकों के लोगों का मन बदला है। स्थानीय समुदायों का सहयोग इस अभियान की सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। अमित शाह ने प्रभावित क्षेत्रों में जनता से सीधे संवाद स्थापित किया है। ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया है, जिससे उनका जीवन स्तर

स नवसलवाद पर लगाम

A group of young people in traditional Indian attire, including men in dhotis and women in sarees, are participating in a cultural performance or parade. They are holding Indian flags and playing instruments like a trumpet and a harmonium. The scene is outdoors with a crowd in the background.

अर्थव्यवस्था बन गई। भारत, दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जो चौथे स्थान वाले जर्मनी को जल्दी ही पीछे छोड़ देगा। दूसरी तरफ जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर अप्रत्याशित रूप से गिरकर 5.4 प्रतिशत पर आ गई, जो सात तिमाहियों में सबसे कम है, जबकि मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से अधिक बढ़ी हुई है। इससे कुछ चिंता जरूर बढ़ी है, लेकिन रिजर्व बैंक ने पुष्टि की कि यह मंदी और मुद्रास्फीति उच्च खाद्य लागतों के कारण है, जो जनवरी-मार्च तिमाही तक सामान्य हो जाएगी। देश में हर दिन औसतन 27 किलोमीटर नई सड़कें बनीं। इस दौरान 79 प्रतिशत भारतीय घरों में नल का पानी पहुंच गया है। रेलवे के विस्तार की दृष्टि से उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल संपर्क पूरा होना एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में परिवहन बेहतर हो गया है। साल का समापन अंतरिक्ष में दो यानों की डॉकिंग के स्पेंडेक्स (स्पेस डॉकिंग एक्सप्रेसिमेंट) मिशन से हो रहा है। दुनिया में सिर्फ तीन देश—

अमेरिका, रूस और चीन के पास ही दो यानों की डॉकिंग की क्षमता है। भारत को अपने स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए इस तकनीक की जरूरत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने इस साल आने वाले वर्षों के अंतरिक्ष मिशनों की एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इसमें चंद्रयान-4, चंद्रयान-5 और गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम शामिल हैं। भारत 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा, वहीं 2040 तक चंद्रमा पर मानव उतारकर इतिहास रचेगा। सितंबर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लेकर कुछ फैसले किए गए। सरकार ने अपने शुक्र ऑर्बिटर मिशन, गगनयान फॉलो-ऑन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ—साथ अगली पीढ़ी के लॉन्च वाहन विकास को भी मंजूरी दी। इस साल लंबी दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण ने भारत की रक्षा तैयारियों को काफी मजबूत किया। इसके अलावा, भारत ने अमेरिका के साथ 3.5 अरब डॉलर का ड्रोन सौदा किया, जिससे तीनों सेनाओं की क्षमता में वृद्धि होगी।

बेहतर हुआ है। स्थानीय सुरक्षा बलों को मजबूत करते हुए उनकी मदद से नक्सलवाद को कमजोर किया गया है। इन प्रयासों ने न केवल जनता का विश्वास जीता है, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और स्थिरता लाने में भी मदद की है। ड्रोन जैसी तमाम तकनीकों के जरिए जहां माओवादियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, वहाँ सटीक सूचनाओं के चलते उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में भी आसानी हुई है। इसके साथ ही नक्सलियों के लिए की जा रही परोक्ष और अप्रत्यक्ष फंडिंग पर नकेल करसी गई है। हालांकि सरकार के इस कदम को लेकर राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना झेलनी पड़ी है। लेकिन केंद्र सरकार ने अपना रुख नहीं बदला। इससे नक्सलियों की आर्थिक रीढ़ कमजोर हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। नक्सलवाद पर नकेल कितना कारगर रहा है, इसका ही असर है कि देश के अब सिर्फ 38 जिले ही नक्सल प्रभावित माने जा रहे हैं, जबकि पहले ऐसे जिलों की संख्या 120 से अधिक थी।

नक्सलवाद से जुड़े सिमटते आंकड़े ही बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की नक्सलविरोधी रणनीति की दिशा सही है। सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15,000 से अधिक आवास बनाए जा रहे हैं। जिनमें विस्थापित परिवारों को रहने की सुविधा दी जा रही है। नक्सलवाद से विस्थापित परिवारों के लिए राहत शिविर भी बनाए गए हैं। समर्पण कर चुके नक्सलियों और नक्सल प्रभावित इलाके के के लोगों को रोजगार दिलाने के लिए कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की गई है, जहां आत्मसमर्पण करने चुके नक्सलियों को उनकी रुचि वाले कारोबार और व्यवसाय के प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही रोजगार मेले भी आयोजित किए जाते रहे। जिनके जरिए सरकारी और निजी, दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता के साथ ही बैंकों से कर्ज भी आसान दर पर दिलवाया जा रहा है। केंद्र सरकार की इन योजनाओं को लागू करने में सरकार ने श्रीलंका और कोलंबिया जैसे देशों में अपनाई गई पुनर्वास नीतियों का भी असर है।

आर्सेनिक की अधिकता से जीवन पर संकट

३८

देश के भूजल में आसनिक वाला लगातार बढ़ती जा रही है। जो देश के 25 राज्यों के लगभग 10 जिले भूजल में बढ़ती आर्सेनिक स्थाया से पीड़ित हैं। दुनिया भर में तो लगभग 50 करोड़ लोग भूजल में आसनिक की समस्या से पीड़ित रहे हैं। इससे पिग्मेंटेशन, इपरकेराटोसिस, अल्सरे शन आदि काँसर, किडनी काँसर, फेफड़ा काँसर के अलावा अब हृदय वर, त्वचा के रंग में परिवर्तन, लियों और तलवों पर सख्त चिह्न, पैरों की रक्तवाहिकाओं और गाशय संबंधी बीमारियां हो रही हैं। वैज्ञानिकों ने आर्सेनिक युक्त खेत पानी पीने से मधुमेह, उच्च रक्तचाप और प्रजनन संबंधी बीमारियों की आशंका भी जताई। देश में कोलकाता का नाम सेनिक से प्रदूषित शहरों में शीर्ष है। इस समय, देश के 25 राज्यों के 469 जिले फ्लोराइड विप्रूषित हैं। भारत में भूजल सेनिक की मात्रा स्वीकार्य सीमा काफी अधिक है, जिससे पश्चिम

माणिपुर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। भारत में आर्सेनिक से प्रभावित लोगों की संख्या 5 करोड़ से अधिक है। आज असलियत में गंगा—मेघना—ब्रह्मपुत्र के मैदान का उत्तराखण्ड से लेकर पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश सहित देश के पूर्वोत्तर के राज्य का भूजल आर्सेनिक से दूषित है। बांग्लादेश, भूजल में सर्वाधिक आर्सेनिक प्रदूषित देशों की सूची में शीर्ष पर है। दरअसल, भूजल में आर्सेनिक की मौजूदगी मुख्यतः 100 मीटर गहराई तक के जल में बनी रहती है। इससे गहरा जल आर्सेनिक से मुक्त रहता है लेकिन सबसे ज्यादा भूजल का उपयोग 100 मीटर तक के जल का होता है, इसलिए इसमें ही आर्सेनिक का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। आर्सेनिक से दूध भी अछूता नहीं है। चूंकि आर्सेनिक युक्त भूजल का उपयोग सिंचाई कार्यों में भी होता है, इसलिए अकार्बनिक तत्व पौधों के शरीर में पहुंचकर जड़ों, तनों और पत्तियों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। और

जाकर जमा हो जाते हैं। दरअसल, पानी में घुलनशील अकार्बनिक आर्सेनिक बहुत ही जहरीला होता है। इसके सेवन से जठरांत्र रोग सम्बन्धी लक्षण से मृत्यु तक हो जाती है। गौरतलब है कि चट्टानों और खनिजों के अपक्षय के दौरान आर्सेनिक मिट्टी और भूजल में प्रवेश करता है। यह मानवजनित स्रोतों से मिट्टी और भूजल में प्रवेश करता है। यह पर्यावरण के लिए भी खतरा है। क्योंकि आर्सेनिक उच्च तापमान प्रक्रियाओं जैसे कि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों, वनस्पतियों को जलाने और ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा वायुमंडल में उत्सर्जित होता है। पानी में विशेष रूप से भूजल में, जहां सल्फाइड खनिज जमा होते हैं और ज्वालामुखीय चट्टानों से निकलने वाली तलछट जमा होती है, आर्सेनिक की सांद्रता काफी बढ़ जाती है। दुनियाभर के जलस्तर में आर्सेनिक की बढ़ती मात्रा के चलते कैंसर के रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया में 2011 और 2019 के दौरान हर

किंसर के मामलों में 11.2 फोसदो की दर से बढ़ोत्तरी हो रही है। वहाँ आर्सेनिक युक्त पानी पीने से किंडनी के कैंसर के रोगियों की

तादाद में 6 फीसदी की दर से



बढ़ोतरी हो रही है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक इसे सातवां सबसे आम कैंसर माना गया है। अमेरिका के टे क्सास स्थित ए एण्ड एम यूनिवर्सिटी स्कूल आफ पब्लिक हैल्थ के वैज्ञानिकों के अनुसार आर्सेनिक युक्त पानी से किडनी के

है। शोध में खुलासा हुआ है कि जिन क्षेत्रों में बसी आबादी जलाशयों, कुएं या फिर नदियों पर निर्भर हैं, वहां कैंसर का जोखिम 22 फीसदी अधिक पाया गया है। रासायनिक तत्व है। इसे जहरीली धातु माना जाता है। पानी से आर्सेनिक हटाने की दिशा में इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों में सोखना, आसवन और आयन एक्सचेंज में रिवर्स आस्मोसिस यानी

सड़क हादसों में पांच लोगों की मौत

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी के विभिन्न थानाक्षेत्रों में हुए सड़क हादसों में पांच लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना पर मृतकों के परिजनों में रोना-पीटना मच गया। लखीमपुर खीरी के निधान निवासी राजा उर्फ पप्पू कश्यप (48) बंधरा के बनी में किराये पर पल्ली चंदा देवी के साथ रहते थे। वह पास में ही बने ढाबे पर काम करते थे। रविवार रात करीब दस बजे वह साइकिल से काम पर जा रहे थे। रास्ते में पिकअप की टक्कर से उनकी मौत हो गई। वहीं, उन्नाव के असोहा में रहने वाली माया देवी (50) सोमवार सुबह बेटे विकास के साथ बाइक से सरोजनीनगर के कंचनपुरी में रहने वाले अपने जीजा से मिलने जा रहे थे। एयरपोर्ट वीआईपी तिराहे के पास एलपीजी सिलिंडर से लड़के की टक्कर से इरफान की मौत हो गई। आरोपी चालक ट्रक छोड़कर भाग निकला। हादसे के कारण लखनऊ से कानपुर जाने वाली पटरी पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने थोड़ी देर में सचिन ने बताया कि बीते बुधसप्तिवार शाम को पिता साइकिल से दूध बेचकर लौट रहे थे। उनके भाई

से माया की मौत हो गई। विकास माझी रूप से चोटिल हो गए। आरोपी चालक डंपर छोड़कर भाग निकला। आलमबाग निवासी इरफान (34) डाला चलाते थे। वह सोमवार शाम करीब 4-015 बजे दोस्त आलमबाग निवासी सर्वेश के साथ बाइक से सरोजनीनगर के कंचनपुरी में रहने वाले अपने जीजा से मिलने जा रहे थे। एयरपोर्ट वीआईपी तिराहे के पास एलपीजी सिलिंडर से लड़के की टक्कर से इरफान की मौत हो गई। आरोपी चालक ट्रक छोड़कर भाग निकला। हादसे के कारण लखनऊ से कानपुर जाने वाली पटरी पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने थोड़ी देर में सचिन ने बताया कि बीते बुधसप्तिवार शाम को पिता साइकिल से दूध बेचकर लौट रहे थे। उनके भाई

समस्त प्रदेश, जनपद एवं ग्राम वासियों को नूतन नव वर्ष की हादिक शुभकामनाएं बधाई



**डॉ. मनीष कुमार मिश्रा
मां विद्यवासिनी
मेडिकल स्टोर वेवा
कौराहा (बजरंगी चौक)
इमरियागंज सिद्धार्थ
नगर
मो- 9918165754**

समस्त प्रदेश, जनपद एवं ग्राम वासियों को नूतन नव वर्ष की हादिक शुभकामनाएं बधाई



**मो मोजम्मिल
ग्राम प्रधान कबूलपुर
विकास खण्ड
सिरकोनी
जनपद जौनपुर**

समस्त प्रदेश, जनपद एवं ग्राम वासियों को नूतन नव वर्ष की हादिक शुभकामनाएं बधाई



**संजय सिंह बब्लू
ग्राम प्रधान
बब्लपुर
विकास खण्ड
सिरकोनी**

समस्त प्रदेश, जनपद एवं ग्राम वासियों को नूतन नव वर्ष की हादिक शुभकामनाएं बधाई



**चंदा यादव पत्नी
मृत्युंजय यादव
ग्राम प्रधान ग्यासपुर
विकास खण्ड
सिरकोनी**

माजपा जिला प्रतिनिधि की सूची में मृत नेता का नाम होने से खलबली, संगठन की कार्यशाली पर उठ रहे सवाल

लखनऊ, (संवाददाता)। भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपी से ही होमरक कर रही है। रायबरेली जो सियासत के लिए जाम देवा के बहेद महत्वपूर्ण है और भाजपा की साख हेमंत से यहाँ के बुनाव में बढ़ती है। पिछले 24 घंटे में एक नए घटनाक्रम से भाजपा जिला संगठन में खलबली मची हुई है। दिल्ली से मंडल अध्यक्ष व प्रतिनिधि 1 की जारी की गई सूची में संजय मौर्य को जिला प्रतिनिधि बना दिया गया है। जबकि संजय की मौत हो चुकी है। हालांकि भाजपा के कुछ नेताओं का दावा है कि सूची में जो नाम है, वह जरूरी नहीं है कि मृत संजय मौर्य को जारी जावा जारी लिस्ट में पार्टी की तरफ से यादव बिरादरी को दरकिनार किया गया इसके अलावा और भाजपा की अन्य जातियों को भी नेताओं का दावा है कि सूची में जो नाम है, वह जरूरी नहीं है कि मृत संजय मौर्य को जारी जावा जारी लिस्ट में जाहं खबर आपत्ति जारी हो रही है। उनके बेटे सचिन ने बताया कि बीते बुधसप्तिवार शाम को पिता साइकिल से दूध बेचकर लौट रहे थे।

संस्तुति पर फाइनल हुई है। जिले में मण्डल अध्यक्ष चुनाव की जिमेदारी राकेश मिश्रा के पास थी। जिला प्रभारी पीयूष मिश्रा और पर्यावरण के रूप में प्रदेश महामंत्री संजय रायबरेली की देखरेख में मण्डल अध्यक्ष का चुनाव में गया है। मण्डल अध्यक्ष के पद में जातीय आधार पर एक समीकरण को खेल साधने की काशिश की गई है। जिसमें विधानसभा वार जारी लिस्ट में पार्टी की तरफ से यादव बिरादरी को दरकिनार किया गया इसके अलावा और भाजपा की अन्य जातियों को भी नेताओं का दावा है कि सूची में जो नाम है, वह जरूरी नहीं है कि मृत संजय मौर्य को जारी जावा जारी लिस्ट में जाहं खबर आपत्ति जारी हो रही है। मण्डल अध्यक्ष और जिला प्रतिनिधियों को जावा जारी लिस्ट पर नाम होने से पार्टी की जमकर किरकिरी

चंद्रिका देवी मंदिर स्थित रेस्टोरेंट में लगी आग, रास्ते पर अतिक्रमण के चलते नहीं पहुंची फाटर बिगड

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ के बड़ी कार्यालय के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में सोमवार की रात लगभग 1:00 बजे आग लग गई। जब तक आग बुझाने का इंतजाम किया गया रेस्टोरेंट का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। सोमवारी



अमावस्या के मौके पर चंद्रिका देवी मंदिर दर्शनों के लिए सोमवार को श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी थी। बताया जा रहा है कि रात लगभग 1:00 बजे मंदिर समिति कार्यालय के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से अपरा तपारी आग गई। मंदिर परिसर में मौजूद संसाधनों से आग बुझाने का प्रयास किया गया लेकिन इसके पहले आग से रेस्टोरेंट का पूरा सामान जल कर खाक हो गया।

व्यापारी नेता पर जानलेवा हमला, बोलेरो सवार हमलावरों ने हॉकी व धारदार हथियार से किया लहूलुहान

लखनऊ, (संवाददाता)। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर कोतवाली और अन्य वस्तुओं से उन पर हमला किया। घटना के बाद हमलावर फरार हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और धायल जगन्नाथ को बिरसिंहपुर अस्पताल ले गए, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें राजकीय मेडिकल ट्राम सेंटर रेफर कर दिया गया। धायल जगन्नाथ के भाई, अमननाथ ने बताया कि गांव में पुरानी रंजिश भी है, उनके भाई को बाजार अध्यक्ष के कारण भी प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने बताया कि अंकित सिंह, मिंटू सिंह, पुनीत सिंह और अमन सिंह के साथ उनके भाई की रंजिश चल रही थी। सोमवार रात बोलेरो सवार लोगों ने उन्हें रोका और फिर एक व्यक्ति ने उन्हें पकड़



एक व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया और तहारीर मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल में पहुंचे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से हमला किया। कोतवाल जयसिंहपुर, अनिलुद्ध सिंह ने कहा कि यह मामला उनके सज्जन में है और तहारीर ये घर जारी हो रहे थे तो बोलेरो सवारों ने इन्हें रोका और लाटी डंडों से पीटा जिससे इनको गंभीर चोटें आई हैं। हमसे इसपाई से बात किया तत्काल पुलिस वहाँ पहुंची और अग्रिम कार्रवाई शुरू की गई है।

ईसाई मिशनरियों इस तरह से कर रही हैं प्रदेश में मतांतरण, अयोध्या के साथ यूपी के इन जिलों में गहरी पैठ

लखनऊ, (संवाददाता)। अवध क्षेत्र में अब नेपाल का मध्येश मतांतरण के लिए ईसाई मिशनरियों को यहाँ मतांतरण के साथ ही वोटिंग पैटर्न बदलने की जिमेदारी सौंपी गई है। मध्येश में सफल इस रणनीति को आगामी चुनाव में यहाँ आजमाया जा सकता है। मिशनरियों को अनुमति दी गई है कि निशाने पर उनकी रायबरेली की रंजिश चल रही थी। सोमवार रात बोलेरो सवार लोगों ने उन्हें रोका और फिर एक व्यक्ति ने उन्हें पकड़

फंड को खर्च किया जा रहा है। निशाने पर उनकी रायबरेली के भक्त हो जाते हैं। इस तरह उन्हें धर्म परिवर्तन की घोषणा की जरूरत नहीं होती और वे कानूनी कार्रवाई से भी बच जाते हैं।

महिलाओं ने पहनावा ही बदल लिया और तहारीर मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल में पहुंचे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से हमला किया। कोतवाल जयसिंहपुर, अनिलुद्ध सिंह ने कहा कि यह मामला उनके सज्जन में है और तहारीर ये घर जारी हो रहे थे तो बोलेरो सवारों ने इन्हें रोका और लाटी डंडों से पीटा जिससे इनको गंभीर चोटें आई हैं। हमसे इसपाई से बात किया तत्काल पुलिस वहाँ पहुंची और अग्रिम कार्रवाई शुरू की गई है।

नेपाल में मतांतरण से सांस्कृतिक पहचान पर संकट गहरा गया है। इससे राष्ट्रीय एकता खतरे में है। मिशनरी गरीब लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर बाद में उनका शोषण कर रही है। यह धार्मिक आजादी का नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर शोषण का मामला है।

ईसाई मिशनरियों की दीर्घकालीन योजना अंकड़ों में भले ही ईसाईयों की जनसंख्या उत्तमी नहीं बढ़ी है। लेकिन, ईसाई मिशनरियों द्वारा इनको गंभीर और पिछड़े समाज को ध्यान में रखकर